पादरी फेरर की गतिविधियां

*397. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने पादरी फेरर को महाराष्ट्र छोड़ कर चले जाने का नोटिस दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने उन पर साम्प्रदायिक भावना पैदा करने, जिसके कारण दंगे हुए थे, तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के आरोप लगाये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने मत व्यक्त किया था कि पादरी फेरर निर्धन व्यक्तियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिये प्रलोभन देता रहा है तथा उसकी गतिविधियां शांति के लिये खतरा थीं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उसे एक महीने के बाद भारत आने की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पादरी फेरर को भारत छोड़ कर चले जाने का एक नोटिस दिया गया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने ऐसा कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया था। फिर भी, जुलाई, 1968 में विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि पादरी फेरर निर्धन व्यक्तियों को ईसाई बनने के लिये प्रलोभन दे रहे थे और उनकी गतिविधियां दंगे उत्पन्न कर रही थीं और इस प्रकार विधि और व्यवस्था की समस्या खड़ी कर रही थीं।

(घ) पादरी फेरर से जाने से पहले यह कहा गया था कि यदि वह एक महीने से अधिक या उसके करीब के अवकाश में विदेश जाना चाहे तो उनके भारत वापस आने में तथा महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य किसी राज्य में जिसे वह स्वीकार हो काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब उनसे आन्ध्र प्रदेश या गुजरात में काम करने के लिये एक वीसा के हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ङ) सरकार को उनके किसी राज्य में, जिसे स्वीकार्य हो, काम करने के लिये वापस आने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने जो जानकारी सदन को दी है, उस जानकारी के बारे में क्या हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री ने खुद की जानकारी प्राप्त कर ली है ? यदि फादर फेरर की हरकतें, जोकि उन्होंने बताई हैं, सही हैं तो फिर केन्द्रीय सरकार को उनके यहां आने पर आपत्ति क्यों नहीं है ? क्या यह सही है कि आपकी तरफ से आन्ध्र गवर्नमेंट से पूछा गया है कि उन को वह अपने यहां आने देने को तैयार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने जो कहा है, वह बिलकुल ठीक बात है, हम लोगों के पास वही सूचना है जो उन्होंने बताई है। जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उन्होंने जब यह दरख्वास्त दी कि वे यहां आकर गुजरात या आन्ध्र में काम करना चाहते हैं तो स्वाभाविक था कि हमने इन दोनों राज्य सरकारों से पूछा कि क्या वे उनको अपने यहां आने की अनुमति देने को तैयार हैं ? अब जैसा उन का जवाब आयेगा, उसी हिसाब से हम इस आवेदन-पत्र पर निर्णय करेंगे।

श्री एस० एम० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । एक बात में पहले बाजा कर देना चाहता हूं कि जहां तक क्रिश्चियेनिटी का सवाल है, मैं जीसस क्राइस्ट को एक महान् व्यक्ति मानता हूं जो मानवता और प्रेम के उच्च शिखर पर पहुंच गये थे, मगर कोई आदमी क्रिश्चियेनिटी के नाम पर इस तरह का कार्य करे, जैसी कि सूचना दी गई है, तो फिर हमारे केन्द्रीय मंत्री को विचार करना चाहिये कि उनको किसी दूसरे राज्य में जाने की इजाजत देना, क्या उसी बीमारी को फिर से पैदा करना नहीं होगा ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, हमारे गृह-मंत्री जी ने भी इस के बारे में एक वक्तव्य दिया था तथा उन सब बातों पर विचार करने के बाद हम ने तय किया था कि वे कुछ समय के लिये भारतवर्ष से चले जायें । उन के जाने के बाद यह तय किया गया कि कोई राज्य सरकार इन सब बातों को जानने के बाद भी सहमति जाहिर करती है अपनी-अपनी जिम्मेदारी पर, तो हम लोग आपत्ति नहीं करेंगे — केवल इतना ही हम लोगों का विचार है ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : I had been to those areas myself to know the truth and I had gone and visited many villages. I have seen that Father Ferrer has done wonderful work in the field of education, in the field of medical aid, etc.

MR. SPEAKER : You are giving information now. This is question hour.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : In helping farmers he has done very good work. Only the police and some politicians who were exploiting the backward people are afraid of him. Is it not a fact that the Maharashtra Government was afraid of the popularity and not of his work ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : This allegation is incorrect; there is no basis for making such an allegation.

SHRI LOBO PRABHU : This question is slightly embarrassing for me. But I should like to preface it by informing the House that in doing good, I have never regarded my religion as different from the religion of others.

There are friends here who will tell you that in Gorakhpur I was the first one to project the Gita Press as a social force.

MR. SPEAKER : Come to the question.

SHRI LOBO PRABHU : I put up a statue of Tulsidas in 1942 at Soron in Etah. If I ask this question, I ask this quesiton as an Indian. The question is, will the Home Ministry please confirm that Father Ferrer has not made a single conversion by lure of anything, and secondly, will the Home Ministry please confirm that Father Ferrer has done the most valuable work, in fact work which has not been touched by Government, in respect of the development of the villages ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is impossible for us to confirm that he did not use unethical means to gain conversions there. It is not possible for us to confirm it because we have reports to the contrary. (*Interruptions*). He might have done some good job in that area; but we are not saying that he has done everything bad; he might have done some good things, and that is why we say that if any State Government is prepared to take him we shall have no objection.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : What is the normal procedure that is followed when a foreign missionary wants to come here and settle in any particular State ? Does the Government of India grant him permission direct, or does he apply for permission from the State Government ? If it is to be a permission from the Government of India, then why is permission sought from the Maharashtra and Gujarat Governments ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The normal practice that is followed here is, whenever an application is received, we always consult the State Government concerned. Suppose a foreign missionary wants to work in a particular area, we always consult the local administration, that is, the State Government, before we take a decision in the matter.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, फादर फेरर की लोबी बहुत एक्टिव है । उन्होंने अखबार वालों को समाचार छापने

के लिये, लोगों को हवाई जहाज से बुलाने के लिये, तरह-तरह के प्रलोभन दिये हैं और और लाखों रुपया खर्च किया है। यहां पर होम मिनिस्टर महोदय ने एक बार फौरन-क्रिश्चियन्ज के लिये एक स्टेटमेंट दिया था। जिस में उन्होंने कहा था कि अगर किसी फौरन-क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटी आब्जैक्शनेबिल होगी या ऐसा मालूम होगा कि आब्जैक्शनेबिल है तो उस पर कार्यवाही की जायगी—ऐसी स्थिति में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस व्यक्ति की एक्टीविटी को आब्जैक्शनेबिल बताया है और आप भी यही कहते हैं कि हमारे पास और कोई सूचना नहीं है, तो फिर उन को भारत में दोबारा क्यों आने दिया जा रहा है। आपने जो पालिसी डिक्लेयर की थी, आप उस पर क्यों खड़े नहीं रहना चाहते हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इस के बारे में पहले ही साफ तौर से कहा है कि उन की जो गतिविधियां थीं, वे आपत्तिजनक थीं, इसी कारण महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सिफारिश मन्जूर कर के हम ने उन से कहा कि वह भारत के बाहर हौली-डे पर चले जायें। जब उन्होंने वापस लौटने के लिये वीसा की दरख्वास्त दी और कहा कि मैं गुजरात या आन्ध्र में काम करना चाहता हूं, हम ने इन दोनों राज्य सरकारों से पूछा है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह पूछा था कि होम मिनिस्टर ने जो पालिसी डिक्लेयर की थी आप उस के मुताबिक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी कार्यवाही बिलकुल उसी पालिसी के अन्तर्गत है। गुजरात सरकार ने हम से कहा है कि वे फादर फेरर को अपने यहां लेने के लिये तैयार नहीं हैं। अब हम ने आन्ध्र सरकार से पूछा है, अगर वे उन को लेने के लिये तैयार हो जाते हैं, तब हम इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है।

MR. SPEAKER : Shri Kartik Oraon; don't get excited!

SHRI KARTIK ORAON : Everybody has a birthright to have his or her own opinion, but no one has a right to be wrong in relation to facts. Some people, or the Government, may or may not accept, but the fact remains that conversion is always an act of coercion, compulsion, necessity and duress; it is one of undue influence, either directly or indirectly, express or implied. I would like to know from the Government whether they are aware that in allowing the foreign missionaries to stay in our country, they are accepting the existence of a vacuum where they should have stepped in, but on account of their failure to do so, foreign missionaries are coming and working, by way of social work if not by way of religious propagation. It is also reported that quite a number of affidavits have been received that the Maharashtra Government have given aid for welfare work and such aid has been utilised for the purpose of proselytisation. I want to know from the Government as to what is the exact position. Is it not a fact that in allowing this they are throwing an aspersion and making a sad commentary on the performance of the Social Welfare Ministry? I want to know whether they have accepted this as a foreign collaboration for the development of a foreign religion on Indian soil?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH) : I protest very strongly against this. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : She should not take it seriously.

SHRIMATI JAHANARA JAIPAL SINGH : He was given information within my hearing. He was told to ask this question. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : All of you may kindly sit down. The Hon. Lady Member may also sit down. We have heard your protest. The hon. minister has heard your protest. I am sure the Government also would have noted your protest.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : We do not give to anybody, including members of Parliament, information which is of a classified nature and which is secret. But if Members of Parliament ask for information which is not secret we are duty

bound to give that information. I have done nothing which is wrong. If the hon. member asks for information which is not classified and not secret, I will not be justified in withholding that information from him. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : May I request all of you to sit down ? She was only protesting that information was being given to the hon. member to put a supplementary.

SHRI V. KRISHNAMOORTHI : She can protest to the Prime Minister. How can she protest in the Lok Sabha ? (*Interruptions*).

MR. SPEAKER : That is their business. They will take care of themselves. She was only protesting against the way somebody was provoking somebody to put a question by giving information. Now, Short Notice Question, Shri R. Barua.

SHRI K. SURYANARAYANA : On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER : In Question Hour, there is no point of order. Please do not make matters worse.

SHORT NOTICE QUESTION

STRIKE THREAT BY PORT AND DOCK WORKERS

\+

SNQ 3. SHRI N. K. SANGHI :
SHRI R. BARUA :

Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reported statement of the President of the All India Port and Dock Workers Federation saying that port and dock workers in eight major ports of the country will go on an indefinite strike in August, 1968 in case the Wage Board does not evolve a satisfactory fair wage structure;

(b) if so, the main demands of the port and dock workers and whether Government have made efforts to reach an amicable solution to avoid the threatened strike by the workers; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF TRANSPORT AND SHIPPING (DR. V. K. R. V. RAO): (a) to (c). The Wage Board for Port and Dock Workers is at present engaged in having its final discussion before formulating their proposals for a satisfactory wage structure. The President of the All India Port & Dock Workers' Federation, Shri S. R. Kulkarni, is himself a member of the Board, as also Shri Makhan Chatterjee, General Secretary of the Federation.

The Working Committee of the Federation passed a resolution in June 1968 complaining that the Wage Board had already taken 3¼ years and alleging "lack of earnestness on the part of the employers of port and dock workers in finalising the work of the Board". I received a copy of the resolution from the Federation on 3rd July. In reply, the Federation was informed while Government was confident that the port authorities were quite earnest about ensuring that the work of the Wage Board was completed at an early date, Government had sent a fresh instruction to the Major Port Authorities that all efforts should be made to ensure that the work of the Board was not held up for lack of any effort on their part.

Since then, the Federation have held a special Convention in Calcutta on the 24th & 25th July and passed a resolution calling upon its affiliates to organise a whirl-wind agitation for achieving a revised structure of wages, based on fair wage principles, as per the terms of reference of the Wage Board and alleged that this was being thwarted by vested interests.

The Convention authorised the Working Committee of the Federation to organise a strike at all the major ports on or from any day after the 20th August, 1968, after due notice, if in its considered opinion achievement of a reasonable revised wage structure is not feasible of early fulfilment through the Wage Board, because there is inadequate or tardy response to the advice given by the Transport Ministry, as stated in its letter dated 10-7-68, to the Federation *viz.* "Government has already informed the Major Port Authorities that all efforts should be made to ensure that the work of the Board is not held up for lack of any efforts on the part of Port Authorities".

A copy of the resolution has been sent to my Ministry.

I do not understand this attitude. As I have stated already, the Wage Board is in the final stages of its work. Its last